

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स वालमार्क रियल्टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (वीआरएचपीएल) और कुछ बीबीएमपी अधिकारियों से जुड़े टीडीआर घोटाले के मामले में 14/08/2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। इस घोटाले की कीमत लगभग 4.06 करोड़ रुपये है, जिसमें टीडीआर दलालों और फर्जी मालिकों की जमीन और फ्लैट जैसी अचल संपत्तियां शामिल हैं। टीडीआर/डीआरसी का अर्थ है निर्मित क्षेत्र (बीयूए) को निर्दिष्ट करने वाला एक निर्णय, जिसे किसी साइट या प्लॉट का मालिक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा मुफ्त में भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के कारण छोड़ी गई भूमि के बदले में बेच सकता है या उपयोग कर सकता है - यथास्थान/अन्यत्र, जिसे मास्टर प्लान के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या सड़क चौड़ीकरण, मनोरंजक उपयोग क्षेत्र आदि के लिए अलग रखा जाना आवश्यक है।

ईडी ने एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एसीबी द्वारा एफआईआर में दाखिल आरोपपत्र के अनुसार, आरोपी कंपनी, जिसका प्रतिनिधित्व उसके निदेशक रतन लाठ कर रहे हैं, ने डीआरसी प्राप्त करने के बाद, टीडीआर को रियल एस्टेट कंपनियों और व्यक्तियों को बेच दिया, जिससे कुल 27.68 करोड़ रुपये (लगभग) का अवैध लाभ अर्जित किया गया।

इससे पहले, ईडी, बे.आं.का. ने धोखाधड़ी से टीडीआर जारी करने से जुड़े एक घोटाले के संबंध में मेसर्स वालमार्क रियल्टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय, उसके निदेशक और कुछ बिल्डरों, दलालों और फर्जी टीडीआर आवेदकों सिहत 9 परिसरों की तलाशी ली, जिससे टीडीआर दलालों और पिछले मालिकों की वास्तविक भूमिका का पता चला। पीएमएलए की धारा 17 के तहत जब्त की गई आपितजनक सामग्री अपराध की इन आय (पीओसी) के वितरण की पुष्टि करती है, वीआरएचपीएल ने 17.47 करोड़ रुपये अपने पास रखे, जबिक दलालों सुरेंद्रनाथ, गौतम और सुरेश ने क्रमशः 3.50 करोड़ रुपये, 3.36 करोड़ रुपये और 3.35 करोड़ रुपये अपने पास रखे, और पिछले मालिक स्वर्गीय श्री रेवन्ना के उत्तराधिकारियों को पीओसी में वीआरएचपीएल के हिस्से से लगभग 2.7 करोड़ रुपये मिले। जांच में आगे पता चला कि इन प्राप्तियों को अचल संपित अधिग्रहण और नियमित व्यावसायिक खर्चों में एकीकृत करने से पहले कई खातों के माध्यम से स्तरित किया गया था, जिससे उक्त पीओसी समाप्त हो गया।

अब तक की जाँच से एक सुनियोजित षडयंत्र का पता चला है जिसके तहत दलाल बी.एस. सुरेन्द्रनाथ, के. गौतम और के. सुरेश ने वीआरएचपीएल और बीबीएमपी अधिकारियों के साथ मिलकर पिछले मालिकों के पक्ष में म्यूटेशन हासिल कर लिया, जबिक ज़मीन बहुत पहले ही राजस्व लेआउट में बदल चुकी थी और कई तीसरे पक्ष के खरीदार उस पर कब्ज़ा कर चुके थे। बीबीएमपी द्वारा जारी कई परिपत्रों का उल्लंघन करते हुए, ज़मीन पर वास्तविक कब्ज़ा लेने का कोई प्रयास किए बिना, मनगढ़ंत महाज़रों और मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर टीडीआर जारी किए गए।

इस तरह, बीबीएमपी द्वारा सड़क चौड़ीकरण और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिसूचित कई अन्य स्थलों पर भी टीडीआर धोखाधड़ी की गई है, जिनकी आगे जाँच की जा रही है।